नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 109
दि. 21.01.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ीगत परिवर्तन का संकेत नितिन नवीन के नेतृत्व में नए दौर की शुरुआत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक नया अध्याय उस समय जुड़ गया जब दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित भव्य समारोह में नितिन नवीन ने भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। महज 45 वर्ष की आयु में इस सर्वोच्च सांगठनिक जिम्मेदारी को संभालने वाले नितिन नवीन भाजपा के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। यह केवल एक औपचारिक पदग्रहण नहीं था, बल्कि संगठन के भीतर पीढ़ीगत बदलाव, नेतृत्व के नए मॉडल और कार्यकर्ता-आधारित संस्कृति के पुनर्स्मरण का प्रतीक भी बन गया। समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे, जिससे यह स्पष्ट था कि भाजपा इस बदलाव को एक उत्सव और संगठनात्मक पर्व के रूप में देख रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन पूरे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु रहा। उन्होंने नितिन नवीन को न केवल शुभकामनाएं दीं, बल्कि मंच से ऐसा संदेश भी दिया जिसने पूरे राजनीतिक विमर्श में हलचल पैदा कर दी। प्रधानमंत्री ने हँसते हुए कहा कि पार्टी के मामलों में अब नितिन नवीन उनके भी बॉस हैं और वे स्वयं एक कार्यकर्ता की भूमिका में हैं। यह वक्तव्य केवल शाब्दिक विनोद नहीं था, बल्कि भाजपा की उस परंपरा का दोहराव था जिसमें पद से ऊपर संगठन और व्यक्ति से ऊपर व्यवस्था को रखा जाता है। प्रधानमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से नितिन नवीन को मिठाई खिलाई और उनके कंधे पर हाथ

रखकर यह जताया कि पार्टी नेतृत्व उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा है।

नितिन नवीन का निर्वाचन पूरी तरह निर्विरोध रहा, जिसे भाजपा की आंतरिक एकजुटता और संगठनात्मक अनुशासन का उदाहरण माना जा रहा है। संगठन पर्व के समापन के बाद हुई चुनाव प्रक्रिया में केवल उनका ही नामांकन दाखिल हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। इस प्रक्रिया ने यह भी स्पष्ट किया कि नितिन नवीन का चयन केवल आयु या प्रतीकात्मक युवा चेहरे के कारण नहीं, बल्कि उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव, राजनीतिक परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर हुआ है।

पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले संबोधन में नितिन नवीन भावुक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उनके लिए राजनीति सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा की साधना है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ताओं और मार्गदर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे स्वयं को आज भी एक साधारण कार्यकर्ता ही मानते हैं और उसी भावना के साथ संगठन को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। उनका यह वक्तव्य भाजपा की मूल विचारधारा से जुड़ाव को दर्शाता है, जिसमें कार्यकर्ता सर्वोच्च माना जाता है और नेतृत्व सेवा का माध्यम होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में नितिन नवीन को युवा ऊर्जा और गहरे संगठनात्मक अनुभव का संगम बताया। उन्होंने कहा कि नवीन उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने बदलते भारत, तकनीकी क्रांति और सामाजिक परिवर्तन को करीब से देखा है। मोदी ने यह भी कहा कि भाजपा को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो डिजिटल युग की चुनौतियों को समझता हो और युवाओं से संवाद करने की क्षमता रखता हो। अपने चिर-परिचित अंदाज में उन्होंने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि अब अध्यक्ष जी उनकी भी गोपनीय रिपोर्ट लिखेंगे, जिस पर पूरा सभागार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। यह क्षण मंच पर मौजूद वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच आत्मीयता और सहजता का प्रतीक बन गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्ममंथन की क्षमता है। पार्टी हर चुनाव के बाद अपनी जीत और हार दोनों का विश्लेषण करती है, गलतियों से सीखती है और आगे की रणनीति तय करती है। इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसे दल अपने पतन के कारणों पर गंभीरता से विचार नहीं करते, जिससे वे समय के साथ अप्रासंगिक होते चले जाते हैं। मोदी ने यह भी कहा कि भाजपा एक जीवंत संगठन है, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता रखता है।

नितिन नवीन ने अपने भाषण में विशेष रूप से युवाओं का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजनीति को अक्सर त्वरित सफलता या शॉर्टकट के रूप में देखा जाता है, जबकि वास्तव में यह एक लंबी यात्रा है। उन्होंने राजनीति की तुलना सौ मीटर की दौड़ से नहीं, बल्कि मैराथन से की, जिसमें धैर्य, निरंतरता और समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे राजनीति को करियर नहीं, बल्कि समाज और देश की सेवा का माध्यम मानें। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आने वाले विधानसभा चुनावों, विशेषकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में अभी से पूरी तैयारी के साथ जुट जाने का आह्वान किया।

वायरल वीडियो विवाद के बाद कर्नाटक के डीजीपी के. रामचंद्र राव निलंबित, सरकार ने जांच के दिए आदेश

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए डीजीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. के. रामचंद्र राव को निलंबित कर दिया है। रामचंद्र राव राज्य में डीजीपी (सिविल राइट्स एनफोर्समेंट) के पद पर कार्यरत थे। यह कार्रवाई एक कथित अश्लील वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई, जिसमें अधिकारी को कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाए जाने का दावा किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद राज्य की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई थी। सोमवार 19 जनवरी को वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों के भीतर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार कोई भी गलत आचरण बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद गृह विभाग ने मामले की समीक्षा कर निलंबन का आदेश जारी किया।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि डॉ. के. रामचंद्र राव का आचरण एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के पद और गरिमा के अनुरूप नहीं पाया गया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल

सेवा नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि इससे सरकार और पुलिस विभाग की छवि को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। सरकार ने प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर यह माना है कि जब तक मामले की विस्तृत जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें पद पर बने रहना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन आदेश के अनुसार, जांच लंबित रहने की अवधि के दौरान डॉ. रामचंद्र राव राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही उन्हें सेवा नियमों के तहत मिलने वाले दायित्वों और अधिकारों से भी फिलहाल दूर रखा गया है। सरकार ने संकेत दिया है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके।

वीडियो सामने आने के बाद डॉ. रामचंद्र राव ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया था। गृह मंत्री जी. परमेश्वर से मिलने के लिए वह उनके आवास पहुंचे थे, हालांकि उस समय मुलाकात नहीं हो सकी। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया था कि वायरल वीडियो पूरी तरह झूठा और मॉर्फ्ड है। उन्होंने कहा था कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि यह वीडियो कब और कैसे बनाया गया। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि इस पूरे मामले में कानूनी सलाह ली जाएगी और आगे की रणनीति वकीलों से चर्चा के बाद तय की जाएगी।

पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या यह वीडियो पुराना हो सकता है, डीजीपी ने कहा था कि अगर पुराना माना जाए तो यह आठ साल पहले का हो सकता है, जब वह बेलगावी में तैनात थे। हालांकि उन्होंने फिर दोहराया कि वीडियो से उनका कोई लेना-देना नहीं है और यह उन्हें बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। उनका कहना था कि आज के दौर में तकनीक के जरिए किसी के खिलाफ कुछ भी गढ़ा जा सकता है।

इस मामले पर राज्य सरकार के अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर ने कहा कि सरकार किसी को भी कानून से ऊपर नहीं मानती। यदि किसी ने गलत किया है, चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा साफ है।

गौरतलब है कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब कर्नाटक सरकार प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर लगातार जोर दे रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जुड़ा यह विवाद न केवल पुलिस विभाग की साख से जुड़ा है, बल्कि सरकार की कार्यशैली की भी परीक्षा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और सरकार आगे क्या कदम उठाती है।

ऑस्ट्रेलिया में नफरती भाषण और हथियार नियंत्रण के सख्त कानून पारित, बॉन्डी बीच हमले के बाद सरकार का बड़ा कदम

(जीएनएस)। मेलबर्न। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने नफरती भाषण और हथियार नियंत्रण से जुड़े दो अहम विधेयकों को पारित कर दिया है। ये कानून पिछले महीने सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान यहूदी समुदाय पर हुए जानलेवा हमले की पृष्ठभूमि में लाए गए थे। सरकार का कहना है कि इन नए प्रावधानों का उद्देश्य कट्टरपंथी विचारधाराओं पर लगाम लगाना, हथियारों पर सख्त नियंत्रण स्थापित करना और भविष्य में इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोकना है।

शुरुआत में सरकार ने नफरती भाषण और हथियार नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों को एक ही कानून के तहत लाने की योजना बनाई थी, लेकिन संसद में व्यापक चर्चा के बाद इन्हें दो अलग-अलग विधेयकों के रूप में पेश किया गया। सीनेट में हथियार नियंत्रण संबंधी विधेयक 38 के मुकाबले 26 मतों से पारित हुआ, जबकि नफरती भाषण से जुड़ा कानून 38-22 मतों के अंतर से मंजूर किया गया। नए हथियार नियंत्रण कानून के तहत आम नागरिकों के लिए बंदूक रखने की सीमा तय कर दी गई है। अब सामान्य नागरिक अधिकतम चार हथियार ही रख सकेंगे, जबकि किसानों को उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 10 हथियार रखने की अनुमति दी गई है। इसके

साथ ही सरकार ने गन बायबैक योजना को भी मजबूत किया है, जिसके तहत आम लोगों से हथियार खरीदे जाएंगे ताकि समाज में अवैध या अनावश्यक हथियारों की संख्या कम की जा सके। सरकार का मानना है कि इससे न केवल अपराधों में कमी आएगी, बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली हिंसक घटनाओं पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा।

नफरती भाषण से जुड़े कानून के तहत सरकार को ऐसे कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिलेगा, जो भले ही आतंकवादी संगठनों की कानूनी परिभाषा में सीधे तौर पर न आते हों, लेकिन समाज में नफरत, हिंसा और कट्टरता को बढ़ावा देते हों। इस कानून के दायरे में हिज्ब-उत-तहरीर जैसे इस्लामी संगठन भी शामिल हैं, जिन पर पहले से ही कई देशों में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सरकार का कहना है कि यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए नहीं, बल्कि नफरत फैलाने वाली गतिविधियों और हिंसा के उकसावे को रोकने के लिए उठाया गया है।

गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने संसद में चर्चा के दौरान कहा कि यदि ये कानून पहले से लागू होते, तो बॉन्डी बीच हमले में शामिल साजिद अकरम और उसका बेटा नवीद अकरम हथियार रखने के पात्र ही नहीं होते। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हथियार गलत हाथों में न जाएं और कट्टरपंथी सोच को समय रहते रोका जा सके।

बॉन्डी बीच हमला 14 दिसंबर को उस समय हुआ था, जब वहां हनुक्का उत्सव मनाया जा रहा था। इस हमले में साजिद अकरम पुलिस कार्रवाई में मारा गया था, जबकि उसका बेटा नवीद अकरम घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। नवीद अकरम पर 15 हत्या के आरोप सहित कई गंभीर धाराओं और आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना ने पूरे ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा व्यवस्था और नफरती विचारधाराओं पर गंभीर बहस छेड़ दी थी।

सरकार का कहना है कि नए कानूनों के लागू होने से न केवल हथियारों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी, बल्कि ऐसे संगठनों और व्यक्तियों पर भी कार्रवाई संभव होगी जो समाज में नफरत और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन कदमों से भविष्य में इस तरह के हिंसक और आतंकवादी हमलों की संभावना कम होगी और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।

ऑस्ट्रेलिया में इन कानूनों को सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा, ताकि कानून सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाएं, बल्कि जमीन पर भी उनका असर दिखे।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संकट या प्रशासनिक कार्रवाई, पंजाब केसरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब केसरी समूह को बड़ी अंतरिम राहत दी है। प्रिंटिंग प्रेस की बिजली काटे जाने के बाद अखबार के प्रकाशन पर संकट गहराने की आशंका के बीच शीर्ष अदालत ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि पंजाब केसरी का प्रिंटिंग प्रेस बिना किसी बाधा के संचालित होता रहेगा और समूह की अन्य संपत्तियों के मामले में भी यथास्थिति बनी रहेगी। अदालत का यह अंतरिम आदेश हाई कोर्ट के फैसले के एक सप्ताह बाद तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश को मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगलवार को पंजाब केसरी समूह की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। रोहतगी ने अदालत को बताया कि अखबार द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ एक समाचार लेख प्रकाशित किए जाने के बाद समूह के प्रिंटिंग प्रेस और होटल पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई, जिसके तहत बिजली कनेक्शन काट दिया गया। उनका तर्क था कि किसी समाचार या लेख से असहमति के आधार पर किसी मीडिया संस्थान को इस तरह दंडित नहीं किया जा सकता और यह सीधे-सीधे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में इस दलील को गंभीरता से लेते हुए कहा कि समाचार पत्र का प्रकाशन रुकना लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। अदालत ने माना कि प्रिंटिंग प्रेस की बिजली काटे जाने से अखबार के छपने पर प्रतिकूल असर पड़ता है और यह स्थिति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। इसी आधार पर अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए प्रिंटिंग प्रेस के संचालन को जारी रखने का निर्देश दिया।

इस मामले ने उस बहस को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है, जिसमें सरकार और मीडिया के संबंधों, आलोचनात्मक पत्रकारिता और प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग के आरोप बार-बार सामने आते रहे हैं। पंजाब केसरी समूह का दावा है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से प्रतिशोधात्मक है और इसका उद्देश्य सरकार की आलोचना करने वाले अखबार को दबाव में लाना है। समूह की ओर से यह भी कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट समय रहते हस्तक्षेप नहीं करता, तो लाखों पाठकों तक अखबार की पहुंच बाधित हो सकती थी और सैकड़ों कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर भी संकट आ जाता। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में यह भी कहा कि यदि किसी लेख में तथ्यात्मक गलती है या सरकार को आपत्ति है, तो उसके लिए कानून में अलग रास्ते मौजूद हैं, जैसे मानहानि का मामला या स्पष्टीकरण की मांग। लेकिन सीधे तौर पर प्रिंटिंग प्रेस की बिजली काट देना और अखबार के संचालन को प्रभावित करना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि खतरनाक परंपरा की शुरुआत भी हो सकती है। उनका कहना था कि अगर इस तरह की कार्रवाइयों को वैध मान लिया गया, तो भविष्य में कोई भी सरकार असहमति की आवाज को इसी तरह दबा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब केसरी समूह ने राहत की सांस ली है। समूह के भीतर यह आदेश न केवल व्यावसायिक संकट से उबरने का अवसर माना जा रहा है, बल्कि इसे प्रेस की स्वतंत्रता के लिए नैतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है।

इमरान खेमे की रणनीतिक बढ़त, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की कमान संभालेंगे राजा नासिर अब्बास

(जीएनएस)। इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सियासत में एक अहम मोड़ तब देखने को मिला जब उच्च सदन सीनेट में मजलिस वाहदत-ए-मुस्लिमीन (एमडब्ल्यूएम) के नेता राजा नासिर अब्बास को औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया गया। यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है, जब जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रत्यक्ष सत्ता से बाहर होने के बावजूद राजनीतिक मोर्चे पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती नजर आ रही है। सीनेट सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि सीनेट अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी ने नियमों के तहत राजा नासिर अब्बास को तत्काल प्रभाव से विपक्ष का नेता घोषित किया है।

राजा नासिर अब्बास का विपक्ष का नेता बनना केवल एक संसदीय पद का बदलाव नहीं है, बल्कि इसे पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता संरचना और विपक्ष की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले वर्ष नासिर अब्बास को पीटीआई के समर्थन से सीनेट सदस्य चुना गया था। तब से लेकर अब तक वे लगातार इमरान खान के राजनीतिक दृष्टिकोण के करीब माने जाते रहे हैं। ऐसे में सीनेट जैसे महत्वपूर्ण सदन में विपक्ष की अगुवाई उनके हाथ में आना, पीटीआई के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है, खासकर उस स्थिति में जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जेल में है और संगठन पर लगातार दबाव बना हुआ है।

पाकिस्तान की राजनीति में यह संदेश साफ तौर पर जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी अपने सहयोगियों के जरिए संस्थागत राजनीति में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश में जुटी है। कुछ ही दिन पहले नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता के तौर पर पशतूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के प्रमुख महमूद खान अचकजई की नियुक्ति भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अब ऊपरी सदन में राजा नासिर अब्बास की ताजपोशी से यह साफ हो गया है कि पीटीआई अपने सहयोगी दलों को आगे कर सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की नीति पर चल रही है।

राजा नासिर अब्बास का राजनीतिक सफर भी इस लिहाज से दिलचस्प है कि वे एक ऐसे नेता हैं, जिन्होंने धार्मिक और राजनीतिक दोनों मंचों पर अपनी पहचान बनाई है। मजलिस वाहदत-ए-मुस्लिमीन को आमतौर पर एक धार्मिक-राजनीतिक संगठन के रूप में देखा जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को व्यापक बनाने की कोशिश की है। नासिर अब्बास की नियुक्ति से एमडब्ल्यूएम को भी राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की संभावना जताई जा रही है, खासकर सीनेट जैसे मंच पर, जहां कानून निर्माण और राष्ट्रीय नीतियों पर गहन बहस होती है।

विश्लेषकों का मानना है कि सीनेट में विपक्ष के नेता की भूमिका पाकिस्तान की राजनीति में बेहद अहम होती है। यह पद न केवल सरकार के विधेयकों पर नजर रखने और उनकी आलोचना करने का मंच देता है, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष की सामूहिक आवाज को भी मजबूती प्रदान करता है। राजा नासिर अब्बास से यह उम्मीद की जा रही है कि वे सरकार की आर्थिक नीतियों, सुरक्षा मामलों और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर मुखर भूमिका निभाएंगे। साथ ही, इमरान खान की गिरफ्तारी और पीटीआई नेताओं पर हो रही कार्रवाई को भी वे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश कर सकते हैं।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

गाजा पर ट्रम्प प्रस्ताव यूएन को करेगा कमजोर

नोबेल शांति पुरस्कार की उत्कट अभिलाषा के मोह में अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के तमाम हिस्सों में जारी अशांति पर शांति थोपने की असफल कोशिश करते रहे हैं। कई देशों में टकराव के बाद शांति की स्थापना की असफल कोशिशों के पश्चात अब ट्रंप गाजा में शांति थोपने का उपक्रम कर रहे हैं। गाजा में शांति स्थापना के लिये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित योजना विश्व की नियामक संस्थाओं के ढांचे से बाहर उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप एक महत्वाकांक्षी कदम है। गाजा में शांति बनाये रखने के लिये मुनाफे व व्यापार जैसी प्रक्रिया के रूप में यह प्रयास अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को एक प्रत्यक्ष चुनौती है। जो लंबे समय से दुनिया के सबसे जटिल संघर्षों में से एक गाजा संकट को दूर करने के प्रयासों में लगी हुई हैं। सही मायनों में ट्रंप का यह शांति प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ को दरकिनार करने जैसा है, जिसको लेकर उन्होंने बार-बार नकारात्मक प्रतिक्रिया दी हैं। उनकी दलील है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अक्षम और पक्षपाती है। वह इसमें अत्यधिक नौकरशाही हावी होने के भी आरोप लगाते रहे हैं। निश्चित तौर पर दुनिया की महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र को हांकने का प्रयास करती रही हैं। वे अपने मनमाफिक न होने पर इसे अक्षम बताने लगते हैं। दरअसल, ट्रंप की कोशिश है कि उसकी मनमाफिक क्षेत्रीय शक्तियां और अमेरिका-संगठित पक्षों द्वारा शांति योजना को सिरे चढ़ाया जाए। निश्चित रूप से यह प्रयास सार्वभौमिक बहुपक्षवाद को नकार कर शासन व्यवस्था बदलने का प्रयास ही है। निर्विवाद रूप से जो शांति, बिना वैधता,सहमति और जवाबदेही के थोपी जाती है, वह कभी स्थायी समाधान का वाहक नहीं बन सकती है। ऐसे में किसी भी विश्वसनीय शांति प्रयास के जरिये उन वास्तविकताओं से निपटना होगा, जिन्हें ट्रंप मनमानी व जल्दबाजी में अकसर नजरअंदाज करते रहे हैं। अन्यथा यह कोशिश भी ट्रंप की अन्य कोशिशों की तरह विफल ही साबित होगी। आज गाजा संकट जिस मुश्किल दौर में पहुंच चुका है, उसके लिये जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्रियान्वयन, नागरिकों की सुरक्षा और समावेशी शासन का मार्ग प्रभावी समझौते से सुनिश्चित किया जाए। ऐसे हालात में यदि अमेरिका अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को अधिक महत्व देता है या राजनीतिक अधिकारों के बजाय आर्थिक वादों को प्राथमिकता देता है, तो इस प्रयास में उस जोखिम की आशंका बनी रह सकती है, जो जमीनी वास्तविकताओं के बोझ से ढह सकता है। गाजा में शांति के लिये नये प्रयास कसौटी पर तभी खरे उतर सकते हैं जब इसमें गाजा की वास्तविक आवाज को सुना जाता हो। निश्चित रूप से हिंसा पर काबू पाना प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन नागरिकों के जीवन की गरिमा बनाये रखना और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है। शांति समझौते में यदि स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी होती है तो यह शांति प्रस्ताव एक उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि दशकों से हिंसा व विस्थापन का दंश झेल रहे गाजावासियों के कष्टों को और बढ़ाएगा ही। भारत को इस शांति प्रयासों में शामिल करने का प्रस्ताव अमेरिका की ओर से दिया गया है। भारत वहां सदा से ही द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन करता आया है। निर्विवाद रूप से भारत के जहां इस्राइल से बेहतर संबंध हैं, वहीं विश्वसनीयता अरब देशों में भी बरकरार रही है। गाजा में शांति प्रयासों में लगे अरब देशों के साथ भारत के मधुर संबंध रहे हैं। लेकिन यदि शांति प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को नजरअंदाज किया जाता है तो यह भारत की कूटनीतिक पहल के अनुकूल नहीं होगा। निस्संदेह, भारत हमेशा से ही प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बजाय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये बहुपक्षीय मंचों पर ही भरोसा करता रहा है। ऐसे में गाजा में शांति के लिये पहल वैश्विक राजनीति में ट्रंप-प्रेरित उथल-पुथल को ही दर्शाती है। यदि गाजा में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास संयुक्त राष्ट्र को नजरअंदाज करते हैं, तो यह उस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को कमजोर करने का जोखिम बढ़ाएगा, जिसकी जरूरत समझौते के पूरा होने के बाद शांति बनाये रखने के लिये है।

ममता बनर्जी को केंद्र सरकार से टकराने का बहाना चाहिए

> ममता बनर्जी ने आई-पैक के कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के संबंध में संघीय एजेंसी के खिलाफ दो कोलकाता और बिधाननगर पुलिस ने औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कराई। ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के खिलाफ कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के साथ विरोध मार्च निकाला।

पश्चिम बंगाल देश के लिए ऐसा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। इससे होने वाले राष्ट्रव्यापी नुकसान की ममता बनर्जी सरकार को परवाह नहीं है। ममता बनर्जी का तौर—तरीका ऐसा बन चुका है मानो पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं होकर एक स्वतंत्र देश हो। ममता किसी न किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार से टकराती रही हैं। एक भी मौका केंद्र से टकराव का नहीं छोड़ती है और फिर खुद ही लोकतंत्र खतरे में है का नारा देकर सिर पर आसमान उठा लेती है। नया मामला प्रवर्तन निदेशालय के छापे की कार्रवाई का है। ईडी ने पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दूसरी टीम सॉल्टलेक स्थित दफ्तर पर छापा मारा था। सीएम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट पहुंच गई। जब बाहर निकलीं, तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद ऑफिस भी गईं। उन्होंने कहा- गृहमंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं।ममता बनर्जी ने आई-पैक के कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के संबंध में संघीय एजेंसी के खिलाफ दो कोलकाता और बिधाननगर पुलिस ने औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कराई। ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के खिलाफ कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के साथ विरोध मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी चुनाव से पहले उनकी पाटी तृणमूल कांग्रेस के संवेदनशील दस्तावेज जब्त कर राजनीतिक प्रतिशोध कर रही है। पुलिस ने ममता बनर्जी की शिकायत पर ईडी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर औपचारिक जांच शुरू कर दी। यह मुद्दा कलकत्ता हाईकोर्ट तक गया। कलकत्ता हाइकोर्ट ने रेड मामले में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ईडी ने आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। एजेंसी का कहना था कि पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। कोर्ट ने कहा, जब ईडी ने कुछ भी जब्त न करने की बात की है, तो अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता है। याचिका को खारिज कर दी।

अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर भारतीय न्याय संहिता के तहत 17 अपराधों की सीबीआई जांच की मांग की। याचिका में ईडी ने आरोप लगाया है कि सीएम ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने ईडी की रेड में न सिर्फ बाधा डाली बल्कि अधिकारियों को डरा-धमकाकर सबूतों से छेड़छाड़ की। ममता सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि यह मामला चुनावों के बीच उठाया गया है और इससे राजनीतिक माहौल प्रभावित हो सकता है। ईडी चुनावी डेटा चुराने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सवाल किया, "क्या लॉर्डशिप को लगता है कि हाईकोर्ट न्याय नहीं कर सकता? इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा, "कृपया हमारे मुंह में शब्द न डालें। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले को "गंभीर" करार दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह एक गंभीर मामला है। हम इस पर परीक्षण करेंगे। अदालत ने ईडी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया।

ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से टकराने की फेहरिस्त काफी लंबी है। इसका नमूना कोरोना महामारी में केंद्र के साथ टकराव, अम्फन तूफान को लेकर गृह मंत्री के साथ झगड़ा शामिल है। इस क्रम में बंगाली प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच टकराव को कौन भूल सकता है। बंगाल की सीमा पर नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से आने वाले ट्रकों को लेकर भी केंद्र और बंगाल सरकार के बीच टकराव हुआ था। हुगली के तेलिनीपाड़ा में हुए दंगे को लेकर सोशल मीडिया में सवाल उठाने पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ हुई रिपोर्ट पर राज्य पुलिस ने सांसद अर्जुन सिंह और लॉकेट बनर्जी समेत कई नेताओं पर मामले दर्ज कर एक और टकराव को जन्म दिया था।

टकराव की इस कड़ी में नया मामला पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति का है।राज्य के मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार का कार्यकाल इसी महीने 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। यूपीएससी ने ममता सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट को वापस लौटा दिया। यूपीएससी ने राज्य सरकार की सिफारिश को तकनीकी और कानूनी आधार पर रिजेक्ट कर दिया। दरअसल राज्य सरकार ने नए डीजीपी के चयन के लिए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भेजे थे। लेकिन आयोग ने इस लिस्ट पर विचार करने से ही इनकार कर दिया। यूपीएससी का कहना है कि पुरानी प्रक्रियाओं में कई खामियां छोड़ी गई थीं। इसके चलते वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया को सही नहीं माना जा सकता है। नियमों के मुताबिक सरकार को एक तय समय सीमा के भीतर यह लिस्ट भेजनी चाहिए थी। यूपीएससी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए। अब यह मामला कानूनी पेचीदगियों में बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। सरकार के सामने अब कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। गौरतलब है कि पूर्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आगवानी तक के लिए नहीं आई और ना ही बैठक में शामिल हुई। पीएम का दौरा तूफान यास से हुए नुकसान का आकलन करना था। ओडिशा और बंगाल का दौरा तय हो जाने के बाद, दोनों मुख्यमंत्रियों को साथ ही समय बताया गया था। लेकिन ओडिशा ने उस कार्यक्रम के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जबकि वो पीएम के बंगाल के दौरे से पहले था। ममता बनर्जी का आरोप था कि उन्हें पीएम मोदी का इंतजार करना पड़ा। जबकि पीएम को ही ममता का इंतजार करना पड़ा। पीएम के इंतजार करने की बात तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के ट्वीट से भी पुख्ता हुई थी। ममता बनर्जी अपने हेलीकॉप्टर से उतरकर बैठक की जगह पहुंची जो कि हेलीपैड से सिर्फ 500 मीटर दूर था। पीएम से मिलकर वो 14.35 पर वापस भी चली गयीं। इसलिए वो सिर्फ 500 मीटर चलीं और 25 मिनट में वापस चली गईं। उनका पहले वापस जाना भी प्रोटोकॉल के खिलाफ था। इसलिए बंगाल सरकार का ये दावा गलत है कि ममता ने इंतजार किया बल्कि इसके उलट पीएम को ही इंतजार करना पड़ा था। केंद्र के साथ ममता के टकराव में बड़ा पेंच शारदा चिटफंड घोटाले ने भी बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही सीबीआई के अधिकारी तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल पहुंची थी और उसे राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले सीबीआई अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर के घर घुसने नहीं दिया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद खुद सीएम ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के घऱ पहुंचकर धऱने पर बैठ गईं। शारदा चिट फंड घोटाले की जांच का नेतृत्व कर रहे तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था और इसी मामले में पूछताछ करने सीबीआई वहां पहुंची थी। वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश का दौरा कर रहे थे कि अचानक उनके काफिले पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई। इस पर तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल की ममता सरकार को आड़े हाथ लिया था। दूसरे राज्यों में भी गैरभाजपा सरकारें हैं, किन्तु जिस तरह का विरोध ममता सरकार की तरफ से केंद्र का किया जाता रहा है, उससे साफ जाहिर है कि संविधान में मौजद केंद्र के अधिकारों की उसे परवाह नहीं है। ममता का विरोध ज्यादातर मुद्दों पर कानूनी कम और राजनीतिक ज्यादा नजर आता है।

प्रेरणा

ज्ञान की अनंतता: प्लेटो से सीखें सीखने का सच्चा अर्थ

ज्ञान का महत्व मानव सभ्यता के विकास में हमेशा से सर्वोपरि रहा है। ज्ञान केवल किताबी शिक्षा या तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविक गहराई, अनुभव और जीवन में उसके अनुप्रयोग में छिपी होती है। इस संदर्भ में ग्रीस के महान दार्शनिक प्लेटो का जीवन और उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्लेटो केवल विद्वान नहीं थे, बल्कि ज्ञान की असली अनंतता को समझने वाले ज्ञानी भी थे। उनका दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान के प्रति विनम्र हो और दूसरों से सीखने की निरंतर इच्छा रखे।

प्लेटो का जीवन लगातार सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से भरा रहा। वह हर क्षण कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके पास विभिन्न प्रकार के लोग आते थे—शिक्षक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और जिज्ञासु—जो अपनी जिज्ञासा और ज्ञान बढ़ाने की लालसा लेकर उनके पास आते। प्लेटो उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते और अपनी समझ साझा करते, लेकिन साथ ही उनसे कुछ नया सीखने का प्रयास भी करते। उनके लिए ज्ञान का स्रोत किसी की प्रतिष्ठा या पद से निर्धारित नहीं होता था, बल्कि उस व्यक्ति की सोच और अनुभव से तय होता था। यही प्लेटो की सबसे बड़ी विशेषता थी।

एक उदाहरण इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक दिन प्लेटो ने विज्ञान के एक शिक्षक की अध्यात्म संबंधी जिज्ञासा का समाधान किया। शिक्षक ने अपनी समस्या के समाधान के लिए प्लेटो से मार्गदर्शन मांगा और प्लेटो ने उसे स्पष्ट उत्तर दिया। अध्यात्म और तर्क के इस मिश्रण में शिक्षक संतुष्ट हुआ। शिक्षक के जाने के बाद प्लेटो ने उससे यह पूछा कि वह विज्ञान संबंधी कुछ नया सिखाए। शिक्षक आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि इतना बड़ा दार्शनिक, जिसने ज्ञान की उच्चतम उपलब्धि प्राप्त की है, दूसरों से सीखने का प्रयास क्यों कर रहा है।

इस घटना के बाद शिक्षक के शिष्य ने प्लेटो से प्रश्न किया, "सर! आप संसार के प्रसिद्ध दार्शनिक और विद्वान हैं। जब आप आगंतुकों से प्रश्न पूछते हैं, तो हमें यह असहज महसूस होता है। आप इतने ज्ञानी होने के बावजूद दूसरों से सीखते क्यों हैं?" शिष्य की यह जिज्ञासा सहज और मानव स्वाभाविक थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि प्लेटो जैसे महान दार्शनिक के लिए दूसरों से सीखना क्यों आवश्यक है। प्लेटो ने सरल और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, "वत्स, ज्ञान अथाह है। उसकी कोई सीमा नहीं होती। मेरा ज्ञान भी उतना ही सीमित है, जितनी समुद्र की एक बूंद। पूर्ण ज्ञानी होने का दावा कोई नहीं कर सकता। जो ऐसा करता है, वह झूठा और अहंकारी होता है।" इस उत्तर में न केवल ज्ञान की अनंतता का भाव व्यक्त हुआ, बल्कि अहंकार से मुक्त रहने का महत्वपूर्ण संदेश भी समाहित था। प्लेटो हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान का असली मूल्य केवल तथ्यों और सूचनाओं में नहीं, बल्कि विनम्रता और सीखने की निरंतर प्रक्रिया में निहित है।

ज्ञान की यात्रा में विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उसने सारी विद्या अर्जित कर ली, तो वह वास्तविकता से कोसों दूर है। हर विज्ञान, हर दर्शन और हर अनुभव का क्षेत्र निरंतर विकसित होता रहता है। जैसे समुद्र में हर बूंद अलग होती है, वैसे ही ज्ञान की हर नई खोज और समझ मानव जीवन के लिए नए अवसर और नई सोच लेकर आती है। प्लेटो का यह दृष्टिकोण आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जब दुनिया में सूचना और डेटा की विशाल मात्रा उपलब्ध है। केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे समझने, सही रूप में लागू करने और विनम्रता के साथ साझा करने की कला ज्ञान की सच्ची पहचान है।

प्लेटो यह भी बताते हैं कि ज्ञान केवल पढ़ाई और शिक्षा तक सीमित नहीं है। यह जीवन अनुभव, संवाद और दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाने में भी छिपा है। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखना, चाहे वह छोटा ज्ञान रखता हो या बड़ा, विद्या का असली स्वरूप है। इसी कारण प्लेटो ने अपने ज्ञान को समुद्र की एक बूंद के समान समझा और दूसरों से सीखने में कभी संकोच नहीं किया।

आज के समय में, जब लोग केवल प्रमाणपत्र और डिग्रियों के आधार पर अपने आप को ज्ञानी मानने लगे हैं, प्लेटो का दृष्टांत हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की वास्तविक परख अनुभव और विनम्रता से होती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर नई परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाने की क्षमता रखती है। इस दृष्टि से हम न केवल अपने ज्ञान का दायरा बढ़ा सकते हैं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मूल्यवान योगदान दे सकते हैं।

प्लेटो का जीवन यह भी बताता है कि ज्ञान केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। इसे साझा करना और दूसरों को मार्गदर्शन देना भी विद्या का अनिवार्य हिस्सा है। जैसे प्लेटो आगंतुकों से सीखते थे, वैसे ही उन्हें मार्गदर्शन भी देते थे। इस प्रक्रिया में सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों पक्ष समान रूप से लाभान्वित होते थे। ज्ञान का आदान-प्रदान केवल जानकारी का लेन-देन नहीं, बल्कि मन और चेतना का विस्तार है।

प्लेटो का दृष्टांत यह भी स्पष्ट करता है कि सीखना केवल युवाओं या छात्रों के लिए नहीं है। हर उम्र और हर अनुभव के व्यक्ति के पास कुछ नया सिखाने की क्षमता होती है। इसलिए ज्ञान की अनंतता को अपनाने के लिए केवल खुले मन, विनम्रता और सीखने की इच्छा की आवश्यकता है। यही कारण है कि प्लेटो हमेशा नए दृष्टिकोणों के प्रति सजग और उत्सुक रहते थे।

प्लेटो की यह शिक्षा आज के समय में और भी प्रासंगिक है। आधुनिक दुनिया में, जहां तकनीकी और डिजिटल ज्ञान का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्चा ज्ञान केवल डेटा या सूचना का संग्रह नहीं है। ज्ञान का असली मूल्य उसे समझने, लागू करने और दूसरों के साथ साझा करने में है। इसके बिना ज्ञान केवल आंकड़ों और सूचनाओं का ढेर बनकर रह जाता है।

डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक ब्लैकमेलिंग का वैश्विक फलाफल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित ब्लैकमेलिंग वाली कूटनीतिक रणनीति, विशेष रूप से टैरिफ़ और क्षेत्रीय दावों के माध्यम से, उनके मित्र देश रह रह कर परेशान हो उठते हैं। जबकि अमेरिका के शत्रु देश उनको आंख दिखाकर अपनी मनवाने से भी नहीं चूकते, खासकर चीन, रूस और ईरान जैसे दबंग देश। इससे जहां वैश्विक कूटनीति चौराहे पर खड़ी प्रतीत होती है, वहीं उनकी ढुलमुल नीति व्यापार को गहराई से प्रभावित कर रही है। यही वजह है कि यूरोपीय देश, जापान, भारत आदि अंदर से बेचैन हैं। सच कहूं तो राष्ट्रपति ट्रंफ का यह अव्यवहारिक व मतलबपरस्त रुख आर्कटिक सुरक्षा, नाटो एकता और बहुपक्षीय व्यापार नियमों को खुली चुनौती दे रहा है। सबसे पहले इसी कसौटी पर यूरोप व नाटो देशों से जुड़े ग्रीनलैंड विवाद को समझते हैं, जहां ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की मांग क्या रख दी, उनके इस अटपटी सोच से उनके मित्र भी बौखलाहट दिखाने लगे। जिससे परेशान अमेरिका ने सहयोगी से विरोधी बन रहे आठ यूरोपीय देशों (डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी आदि) पर 10% टैरिफ़ लगाने की धमकी दी है, जो जून 2026 तक 25% हो सकता है। यही वजह है कि यूरोपीय नेता जैसे स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन वील ने सहयोग की बजाय संवाद पर जोर देते हुए इसे स्पष्ट "ब्लैकमेल" करार दिया। वहीं, नाटो प्रमुख मार्क रुटे ने ट्रंप से बातचीत की पुष्टि की, लेकिन आर्कटिक क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका जताई।

जहां तक चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध की बात को इस ब्लैकमेलिंग वाली कसौटी पर कसें तो प्रतीत होता है कि साल 2025 में ट्रंप द्वारा चीन पर 104% टैरिफ़ लगाने को चीन (बीजिंग) ने खुलकर "ब्लैकमेलिंग" बताया और अंत तक लड़ने का वादा किया। चीनी पीएम ली कियांग ने इसे संरक्षणवाद का उदाहरण माना, और प्रतिक्रिया स्वरूप यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही। इससे वैश्विक शेयर बाजारों में मंदी की आशंका बढ़ी, क्योंकि अमेरिका ने 70+ देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ़ लागू किए।

वहीं ट्रंफ की ब्लैकमेलिंग वाली कूटनीति का वैश्विक प्रभाव भी साफ दिख रहा है, क्योंकि उनकी इस रणनीति से नाटो जैसे गठबंधनों में दरार डाल पड़ने लगी है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता के संकेत भी मिलने लगे हैं, क्योंकि 1 फरवरी 2026 की डेडलाइन नजदीक है। यूरोप ने आपात बैठक बुलाई, जबकि भारत जैसे देश भी 26% से 50 प्रतिशत टैरिफ़ का सामना कर रहे हैं। इससे इनकी बेचैनी समझी जा सकती है। कुल मिलाकर, ट्रंफ की ब्लैकमेलिंग वाली कूटनीति सिर्फ अमेरिका-प्रथम नीति को प्राथमिकता देती है, लेकिन इससे बहुपक्षीय संस्थाओं के कमजोर होते चले जाने की आशंका भी निराधार नहीं है।

देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां नाटो पर दबाव बढ़ा रही हैं, खासकर ग्रीनलैंड विवाद और रक्षा खर्च मांग के माध्यम से। इसके वैश्विक दुष्प्रभाव या असर को समझते हुए ही अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्द्ध में खुद को मजबूत करने के लिए बेनेजुएला सम्प्रभुता तहस नहस कांड कांड जैसा दुस्साहस दिखाया। इससे रूस, चीन, भारत, ईरान की फटी पड़ी पैबंद भी सामने आ गई। यह सबकुछ इसलिए किया गया ताकि "अमेरिका फर्स्ट" दृष्टिकोण को और अधिक मजबूत किया जा सके। अमेरिका की यह खुली पहल उसके नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन की एकता को दो टूक चुनौती दे रही है, लेकिन कुछ नाटो सदस्यों ने जिस तरह से अपना रक्षा बजट बढ़ाया है, उससे ट्रंफ का मनोबल बढ़ा है। जहां तक ग्रीनलैंड सम्बन्धी तनाव की बात है तो ट्रंप की ग्रीनलैंड अधिग्रहण जैसी अव्यवहारिक मांग का विरोध होने के बाद अमेरिका ने डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी जैसे नाटो सदस्यों पर भी 10% टैरिफ़ लगाए, जो 25% तक बढ़ सकते हैं। जबकि यूरोपीय देशों ने आर्कटिक में सैन्य तैनाती बढ़ाई, जबकि ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया। इस पर नाटो प्रमुख मार्क रुटे ने ट्रंफ सेवबातचीत की, लेकिन विशेषज्ञ इसे गठबंधन के "सबसे काले घंटे" की संभावना मानते हैं। जहां तक नाटो देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने सम्बन्धी अमेरिकी दबाव की बात है तो ट्रंप ने सदस्य देशों से जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करने की मांग की, जो पहले 2% के वेल्स वादे से दुगुने से भी ऊपर है। उनके दावे के अनुसार, इस दबाव से खर्च बढ़ा, लेकिन यूरोप को अमेरिकी सुरक्षा "ब्लैंक चेक" बंद करने की चेतावनी दी। इससे यूरोपीय नेता नाराज़ हैं, जो नाटो विस्तार (जैसे यूक्रेन) रोकने का संकेत भी देता है।

जहां तक ट्रंफ के ब्लैकमेलिंग वाली कूटनीति के संभावित प्रभाव की बात है तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि उनकी ये नीतियां नाटो में दरार पैदा कर सकती हैं, और ट्रांस-अटलांटिक संबंधों को कमजोर करेंगी।

यही वजह है कि अमेरिकी संसद में नाटो से निकासी के विधेयक आए हैं, हालांकि तत्काल विदड्रॉल नहीं हुआ। कुल मिलाकर, लेन-देन वाली कूटनीति गठबंधन की विश्वसनीयता को खतरे में डाल रही है। जबकि अमेरिकी सोच है कि यूरोप की गफलत में फंसकर रूस और एशिया की चकरघिन्नी में फंसकर चीन से खुली दुश्मनी लेने से बेहतर है कि खुद को पश्चिमी गोलार्द्ध यानी उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के देशों के बीच महफूज रखो और यहां पर यूरोपीय/एशियाई देशों की दाल नहीं गल सके, इस हेतु बेनेजुएला जैसी अप्रत्याशित कार्रवाई करते रहो।

अभियान

भिंड के 'डॉक्टर हनुमान': जहां आस्था बन जाती है उपचार

भारत को आस्था, मंदिरों और आध्यात्मिक चमत्कारों की धरती कहा जाता है। यहां हर गांव, हर नगर और हर कोने में किसी न किसी देव स्थल की ऐसी कथा छिपी होती है, जो मन को विश्वास से भर देती है। इन्हीं आस्थाओं के बीच मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित दंदरौआ धाम का नाम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। यह वह स्थान है, जहां हनुमान जी को केवल संकटमोचक या बल-बुद्धि के देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक "डॉक्टर" के रूप में पूजा जाता है। सुनने में यह बात भले ही अनोखी लगे, लेकिन यहां आने वाले लाखों भक्तों का अटूट विश्वास है कि बजरंगबली इस धाम में स्वयं रोगों का निवारण करते हैं और असाध्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं।

दंदरौआ धाम का यह मंदिर वर्षों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि कलियुग में हनुमान जी साक्षात रूप में अपने भक्तों की रक्षा और उपचार के लिए कहीं न कहीं उपस्थित रहते हैं। भिंड का यह मंदिर उसी विश्वास का सजीव प्रमाण माना जाता है। यहां स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा सामान्य प्रतिमाओं से बिल्कुल अलग है। यह नृत्य मुद्रा में है, जो आनंद, ऊर्जा और जीवन के प्रवाह का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों का कहना है कि इस मूर्ति के सामने खड़े होते ही मन के भीतर एक अजीब-सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है।

इस मंदिर से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा एक साधु शिवकुमार दास की है। कहा जाता है कि वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और जीवन की सारी आशाएं खो चुके थे। चिकित्सा विज्ञान ने भी जब जवाब दे दिया, तब उन्होंने हनुमान जी की शरण ली। मान्यता है कि एक दिन हनुमान जी स्वयं डॉक्टर के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। गले में आला, शरीर पर सफेद कोट और चिकित्सक जैसी वेशभूषा में उन्होंने साधु का उपचार किया और कुछ ही समय में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इसी घटना के बाद से यहां हनुमान जी को "डॉक्टर हनुमान" के नाम से पूजा जाने लगा।

धीरे-धीरे यह खबर दूर-दूर तक फैल गई। जो लोग वर्षों से बीमारियों से जूझ रहे थे, वे आशा की किरण लेकर इस धाम तक पहुंचने लगे। किसी को कैंसर था, किसी को टीबी, किसी को मानसिक अवसाद, तो कोई अज्ञात रोगों से पीड़ित था। भक्तों का अनुभव रहा कि यहां आकर केवल शरीर ही नहीं, मन भी हल्का हो जाता है। लोगों का कहना है कि जैसे डॉक्टर रोगी की नब्ज देखकर दवा देता है, वैसे ही हनुमान जी यहां हर भक्त की पीड़ा समझ लेते हैं। ग्वालियर से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर आज केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विश्वास का चिकित्सा केंद्र बन चुका है। हर मंगलवार और शनिवार को यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में लंबी कतारें लगती हैं। कोई अपनी बीमारी की पर्ची लेकर आता है, कोई नारियल और प्रसाद, तो कोई केवल आंसुओं और प्रार्थनाओं के साथ। यहां आने वाले अधिकतर लोग यह मानते हैं कि उन्हें सबसे पहले मानसिक संबल यहीं मिला। जिस इंसान का मन मजबूत हो जाए, उसका शरीर भी आधा स्वस्थ हो जाता है—यही इस धाम का मूल संदेश है।

मंदिर में पूजा का तरीका भी बेहद अनोखा है। अन्य मंदिरों की तरह यहां केवल आरती और भोग ही नहीं होता, बल्कि हनुमान जी को डॉक्टर के रूप में सम्मान दिया जाता है। कई भक्त अपने मेडिकल कागजात, दवाइयों की पर्चियां और रिपोर्ट भी प्रतिमा के सामने रख देते हैं। उनका विश्वास है कि बजरंगबली स्वयं इन दस्तावेजों को देखकर उपचार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह दृश्य आस्था और आधुनिक चिकित्सा के अद्भुत संगम जैसा प्रतीत होता है।

दंदरौआ धाम केवल शारीरिक रोगों के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक पीड़ा के लिए भी प्रसिद्ध है। आज के समय में जब तनाव, अवसाद और निराशा तेजी से बढ़ रहे हैं, यह मंदिर लोगों को भावनात्मक सहारा देता है। कई लोग बताते हैं कि यहां आने के बाद उनके मन का डर खत्म हुआ, नींद अच्छी आने लगी और जीने की इच्छा दोबारा जाग उठी। शायद यही कारण है कि इस धाम को "मन का अस्पताल" भी कहा जाने लगा है।

मंदिर के पुजारियों का कहना है कि यहां चमत्कार से ज्यादा श्रद्धा काम करती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके भीतर सकारात्मक बदलाव जरूर आता है। हनुमान जी बल, साहस और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। जब भक्त उनके सामने सिर झुकाता है, तो उसके भीतर भी वही ऊर्जा जागने लगती है। यही ऊर्जा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है और व्यक्ति धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगता है।

दूर-दराज से आने वाले भक्त अपने अनुभव साझा करते हैं। कोई बताता है कि वर्षों से चल रही बीमारी अचानक नियंत्रण में आ गई, किसी के ऑपरेशन टल गए, तो किसी को नई जिंदगी मिल गई। वैज्ञानिक दृष्टि से भले ही इन घटनाओं की अलग व्याख्या हो, लेकिन आस्था की दुनिया में ये हनुमान जी की कृपा मानी जाती हैं। भारत जैसे देश में जहां चिकित्सा और विश्वास साथ-साथ चलते हैं, यह धाम दोनों के बीच सेतु का काम करता है।

यह मंदिर सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां आने वाले लोग एक-दूसरे का सहारा बनते हैं। कोई अनजान व्यक्ति दूसरे के लिए दुआ करता है, कोई गरीब मरीज की मदद कर देता है। इस तरह यह स्थान केवल धार्मिक नहीं, मानवीय संवेदनाओं का केंद्र भी बन गया है। लोग यहां से केवल प्रसाद नहीं, उम्मीद लेकर लौटते हैं।

दंदरौआ धाम की लोकप्रियता का एक कारण यहां की सरलता भी है। यहां कोई भव्यता का दिखावा नहीं, न ही महंगे अनुष्ठानों की अनिवार्यता। बस सच्चा विश्वास चाहिए। यही वजह है कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति एक ही पंक्ति में खड़ा होकर "डॉक्टर हनुमान" से प्रार्थना करता है। इस समानता में ही इस धाम की असली ताकत छिपी है।

आज के दौर में जब इंसान केवल दवाइयों पर निर्भर होता जा रहा है, भिंड का यह मंदिर याद दिलाता है कि उपचार केवल गोलियों में नहीं, विश्वास में भी छिपा है। यहां आने वाले कई डॉक्टर भी यह मानते हैं कि मरीज के ठीक होने में मानसिक शक्ति की बड़ी भूमिका होती है। अगर मन मजबूत हो जाए तो शरीर भी उपचार को जल्दी स्वीकार करता है। शायद यही रहस्य है इस धाम की लोकप्रियता का।

समय के साथ यह मंदिर मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। सोशल मीडिया और लोगों के अनुभवों के माध्यम से इसकी ख्याति और बढ़ती जा रही है। हर साल यहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। कई लोग तो इसे मेडिकल टूरिज्म से भी जोड़ने लगे हैं, जहां लोग इलाज के साथ आस्था का सहारा लेने आते हैं।

भिंड के "डॉक्टर हनुमान" यह संदेश देते हैं कि जीवन में उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जहां विज्ञान थक जाए, वहां विश्वास रास्ता दिखा सकता है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि इंसान केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा का भी मेल है, और सच्चा उपचार तभी संभव है जब इन तीनों का संतुलन बने। दंदरौआ धाम आज उसी संतुलन का प्रतीक बनकर लाखों लोगों के जीवन में उजाला भर रहा है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में गति, रेल मंत्री ने वीडियो के जरिए प्रगति दिखाई, 15 अगस्त 2027 से परिचालन का दावा

(जीएनएस)। गुजरात। देश के पहले हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के काम में तेजी देखने को मिल रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को इस प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (OHE) मास्ट लगाने का काम किस गति से चल रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बिजली के तार और ट्रैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को समयबद्ध तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए भरोसेमंद और सुरक्षित पावर सप्लाई सुनिश्चित हो सके। रेल मंत्री ने वीडियो के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर OHE मास्ट लगाने का काम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और प्रोजेक्ट समयानुसार पूरा किया जाएगा। बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन बेहद महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया ट्रेनों को लगातार और निर्बाध विद्युत शक्ति प्रदान करती है, जिससे ट्रेनें उच्च गति पर सुरक्षित और सुचारू रूप से चल सकती हैं। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर विभिन्न अलाइनमेंट वाले हिस्सों में, विशेषकर वायडक्ट वाले क्षेत्रों में OHE मास्ट लगाए जा रहे हैं। ये ऊंचे स्टील स्ट्रक्चर 9.5 से 14.5 मीटर तक की ऊँचाई पर लगाए जा रहे हैं और कुल मिलाकर 20,000 से अधिक मास्ट पूरे कॉरिडोर पर स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक मास्ट को पूरी तरह से ट्रैक्शन पावर सिस्टम के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जिसमें ओवरहेड वायर, अर्थिंग अरेंजमेंट, फिटिंग और ट्रेन ऑपरेशन के लिए आवश्यक सभी एक्सेसरीज शामिल हैं।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में ट्रैक्शन सबस्टेशन (TSS) और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन (DSS) का भी निर्माण किया जा रहा है। यह नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि पूरे कॉरिडोर में ट्रेनों को स्थायी, भरोसेमंद और उच्च-गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। OHE मास्ट न केवल वायर की सही ऊंचाई और टेंशन बनाए रखते हैं बल्कि ट्रेन की सुरक्षा और ऑपरेशन की विश्वसनीयता के लिए भी अहम हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि बुलेट ट्रेन का परिचालन 15 अगस्त 2027 से शुरू किया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद, मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय उल्लेखनीय रूप से घट जाएगा और यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित सेवा मिलेगी। यह प्रोजेक्ट न केवल देश में हाई-स्पीड रेल तकनीक के विकास का प्रतीक है, बल्कि "मेक इन इंडिया" पहल के तहत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को भी मजबूत करता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देश में एडवांस्ड रेल टेक्नोलॉजी को अपनाने और विश्व स्तरीय रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह परियोजना भारतीय रेलवे के भविष्य को नई दिशा देगी और देश में अन्य हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। बुलेट ट्रेन के जरिए यात्रा के समय में भारी कटौती के साथ-साथ यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं, सुरक्षा मानकों और समयबद्ध सेवाओं का लाभ मिलेगा।

रेल मंत्री के अनुसार, प्रोजेक्ट के विभिन्न हिस्सों में काम पूरी गति से चल रहा है। उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग टीमों के लगातार ऑन-ग्राउंड निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के कारण यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी मास्ट और ट्रैक्शन सिस्टम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित हों। इसके साथ ही, इस परियोजना में शामिल स्थानीय कंपनियों और मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों को भी तकनीकी प्रशिक्षण और सहयोग प्रदान किया जा रहा है, ताकि देश में हाई-स्पीड रेल तकनीक का स्थायी आधार तैयार किया जा सके।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू होने के बाद, यह केवल यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी एक बड़ा सुधार साबित होगा। यह प्रोजेक्ट गुजरात और महाराष्ट्र के बीच आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी संबंधों को और मजबूत करेगा और भारत के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के लिए मिसाल कायम करेगा।

17 साल बाद गाजियाबाद से चोरी हुई हथिनी की तलाश में गुजरात जा रही पुलिस, जांच में नया मोड़

(जीएनएस)। गाजियाबाद। भारत में कभी-कभी इतने अजीब और दिलचस्प मामले सामने आते हैं कि उन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। ऐसा ही मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां पुलिस 17 साल पहले चोरी हुई एक हथिनी को बरामद करने के लिए अब गुजरात जाने की तैयारी कर रही है। यह मामला न केवल अद्भुत है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई और राष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन की चुनौतियों को भी उजागर करता है। यह कहानी शुरू होती है असालतपुर निवासी गय्यूर अली से। साल 2000 में गय्यूर अली ने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले से 2.50 लाख रुपये में एक हथिनी खरीदी थी। हथिनी को पालने और संभालने के लिए दो कर्मचारियों—लक्ष्मण और लक्की (निवासी जम्मू-कश्मीर)—को रखा गया। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन 1 जनवरी 2008 को अचानक हथिनी गायब हो गई। आरोप है कि यह दो कर्मचारी हथिनी को लेकर फरार हो गए थे।

हथिनी चोरी होने के बाद गय्यूर ने तत्काल पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उस समय पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। सालों तक अपनी हथिनी की तलाश में गय्यूर ने खुद खाक छानी, और अंततः उन्हें पता चला कि हथिनी जम्मू-कश्मीर में है। जब गय्यूर ने वहां जाकर हथिनी को ढूंढने की कोशिश की, तो स्थानीय लोगों ने उन्हें धमका दिया और हथिनी तक पहुँचने नहीं दिया। यह घटनाक्रम गय्यूर के लिए बेहद निराशाजनक रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कानूनी रास्ते पर चल पड़े। अक्टूबर 2022 में गय्यूर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई चली और सितंबर 2025 तक अदालत के निर्देश पर दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यह मामला वर्षों तक अटका रहा, लेकिन इस बीच पुलिस और प्रशासन ने मामले की गहनता को नजरअंदाज नहीं किया। अब जांच में नया मोड़ आया है। एसीपी शालीमार गार्डन, अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पता चला है कि चोरी हुई हथिनी फिलहाल गुजरात के एक बड़े पार्क में है। गय्यूर अली ने भी इस जानकारी की पुष्टि की है। इसके बाद पुलिस ने उच्च अधिकारियों से अनुमति मांगी है ताकि गुजरात जाकर हथिनी को बरामद किया जा सके और पूरी जांच पूरी हो सके। अनुमति मिलने के बाद पुलिस की विशेष टीम गुजरात रवाना होगी।

यह मामला न केवल हथिनी की चोरी और बरामदगी का है, बल्कि इसने भारत में वन्यजीव संरक्षण और कानूनी प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हथिनी जैसी जंगली और घातक जानवरों की चोरी न केवल संपत्ति के नुकसान का कारण बनती है, बल्कि यह वन्यजीव कानूनों के उल्लंघन और नैतिक जिम्मेदारी की भी चुनौती पेश करती है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके सही मालिक तक पहुँच सुनिश्चित करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है।

पुलिस की गुजरात यात्रा और हथिनी की बरामदगी इस मामले में निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। पूरे इलाके में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार गय्यूर को अपनी 'अमानत' वापस मिल पाएगी या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पुलिस कार्रवाई समय पर और सही तरीके से होती है, तो यह मामला अन्य चोरी हुई और लापता वन्यजीवों के मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि कैसे समय और कानूनी प्रक्रिया में देरी होने पर संपत्ति और जिम्मेदारी के मामलों में जटिलताएँ पैदा हो जाती हैं। गय्यूर अली की कहानी यह भी बताती है कि लगातार संघर्ष, धैर्य और कानूनी रास्ते पर टिके रहने से कई वर्षों बाद भी न्याय और सही वस्तु की वापसी संभव हो सकती है।

अखिलेश यादव ने सांसदों के साथ बनाई 2027 की चुनावी रणनीति, पीडीए समर्थन से सत्ता वापसी का दावा

(जीएनएस)। लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का औपचारिक आगाज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। इस बैठक में सपा अध्यक्ष ने 37 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसदों के साथ मिलकर अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटों की रिपोर्ट ली और संभावित प्रत्याशियों के चयन, संगठन की मजबूती तथा मतदाता सूची में आए बदलावों का गहन अध्ययन किया। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग यानी पीडीए के व्यापक समर्थन से सरकार बनाने का संकल्प ले रही है। बैठक में सांसदों ने विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी संगठन की स्थिति, संभावित मतदाताओं और

प्रत्याशियों के बारे में जानकारी साझा की। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की रिपोर्ट पर विचार करते हुए पार्टी नेतृत्व ने यह आकलन किया कि किन क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम घटे हैं और इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सांसदों ने इस पर सुझाव दिए कि किन इलाकों में अभियान तेज करने की जरूरत है और किन क्षेत्रों में नए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए विशेष रणनीति बनाई जानी चाहिए।

अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने बताया कि इस बार चुनाव की रणनीति का केंद्र पीडीए वर्ग रहेगा, जो वर्तमान समय में उपेक्षा और दबाव का सामना कर रहा है। सांसद आनंद भदौरिया ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 2027 में दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाने का इरादा रखती है और पीडीए वर्ग की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होगी। इस रणनीतिक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, प्रो. रामगोपाल यादव, सांसद डिंपल यादव, रामजी लाल सुमन, नरेश उत्तम पटेल, रूची वीरा समेत पार्टी के सभी सांसद मौजूद थे।

बैठक में चर्चा का एक बड़ा हिस्सा मतदाता सूची में बदलाव और एसआईआर की रिपोर्ट पर केंद्रित रहा। पार्टी नेताओं ने यह तय किया कि जिन क्षेत्रों में मतदाता नामों में कमी आई है, वहां विशेष जागरूकता अभियान चलाकर नए मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने बैठक के बाद एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "सैंतीस जिताएंगे सत्ताइस, हम मिलकर पीडीए सरकार बनवाएंगे। पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे।" इस संदेश के जरिए सपा ने स्पष्ट कर दिया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के व्यापक समर्थन से वह अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता में लौटने का दावा कर रही है।

यह बैठक समाजवादी पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि पार्टी संगठन और सांसदों के बीच तालमेल के जरिए पूरी तैयारी के साथ 2027 के चुनाव में उतरने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी ने हर विधानसभा सीट और संसदीय क्षेत्र का गहन मंथन किया है ताकि मतदाता और संगठनात्मक शक्ति के आधार पर प्रभावी चुनावी अभियान चलाया जा सके। इस रणनीति के जरिए सपा ने यह संदेश दिया कि पीडीए के समर्थन के साथ वह उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार: बरेली बना देश के शीर्ष 40 जिलों में शामिल

(जीएनएस)। बरेली जिले ने अपने प्रशासनिक कार्यों और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के दम पर देशभर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार–2025 के अंतर्गत समग्र जिला विकास श्रेणी में बरेली को देश के 513 जिलों में से शीर्ष 40 जिलों में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि जिले के विकास की दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक टीम की मेहनत का परिणाम है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के कुशल नेतृत्व और टीम की प्रतिबद्धता ने जिले को इस राष्ट्रीय सम्मान के योग्य बनाया। जिले में पेयजल, स्वास्थ्य, महिला और बाल कल्याण, शिक्षा, स्वरोजगार, स्वच्छ ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों में जिस गति से विकास कार्यों का संचालन हुआ, उसने पूरे जिले को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया काफी कठोर और विस्तारपूर्ण थी। हर घर जल, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा योजना, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में जिले के प्रदर्शन को परखा गया। इस मूल्यांकन में यह देखा गया कि योजना केवल कागजों तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी रूप से लागू हुई। बरेली जिले की फील्ड विजिट, नियमित समीक्षा बैठकें और तकनीकी नवाचारों का इस्तेमाल भी जिला प्रशासन की कार्यशैली को और अधिक प्रभावी बनाने में मददगार साबित हुआ। जिले में लीलौर झील के सौंदर्यीकरण जैसे पर्यटन विकास के प्रयासों ने जिले की छवि को और सशक्त किया। इसके अलावा कृषि, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में दिख रही प्रगति ने भी जिले के विकास को मजबूती प्रदान की। इस उपलब्धि के बाद बरेली जिले को 21 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुतीकरण देना है, जिसके अंतिम चरण में चयन होने पर यह जिला पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सुशासन का उदाहरण बन जाएगा। जिले की इस सफलता के पीछे प्रशासनिक टीम, स्थानीय अधिकारियों और ग्रामीण-शहरी कार्यकर्ताओं की मेहनत शामिल है, जिन्होंने हर योजना को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुँचाने के लिए दिन-रात प्रयास किया। बरेली का यह उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि यदि योजनाओं को सही दिशा और पारदर्शी कार्यशैली के साथ लागू किया जाए, तो न केवल जिले बल्कि राज्य और देश की छवि भी मजबूत होती है। यह पुरस्कार बरेली जिले के हर अधिकारी और कार्यकर्ता के समर्पण का परिणाम है, जिसने यह साबित किया कि जब प्रशासनिक निर्णय और जमीनी कार्य एक साथ चलते हैं, तो परिणाम हमेशा सकारात्मक और प्रेरक होते हैं।

सहारनपुर में एक ही परिवार के पांच शव फर्श और बेड पर मिले, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

(जीएनएस)। सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक ही घर में पांच लोगों के मृत्युघटना की खबर ने इलाके में भय और सनसनी फैला दी है। घटना स्थल पर फर्श और बेड पर खून से लथपथ शव पाए गए। मृतकों के सिर पर गोली के निशान थे, जिससे प्रारंभिक तौर पर हत्या या सामूहिक आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। घर को सील कर दिया गया है और सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान अमीन अशोक (40), उनकी पत्नी अंजिता (37), उनकी वृद्ध मां विद्यावती (70) और उनके दो पुत्र कार्तिक (16) और देव (13) के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक अमीन और उनकी पत्नी के शव कमरे के फर्श पर पड़े थे, जबकि विद्यावती और दोनों बच्चों के शव बेड पर पाए गए। घटनास्थल से तीन तमंचे भी बरामद किए गए हैं। अमीन अशोक नकुड़ तहसील में अमीन के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि उन्हें यह नौकरी पिता के निधन के बाद अनुकंपा के आधार पर मिली थी। उनके दोनों बेटे छात्र थे—कार्तिक कक्षा दस और देव कक्षा नौ में पढ़ाई कर रहे थे। पड़ोसियों के अनुसार यह परिवार शांत और मिलनसार था, और किसी प्रकार का पारिवारिक विवाद या कोई बाहरी खतरा दिखाई नहीं देता था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिल रहा है कि अमीन ने पहले अपने परिवार के अन्य सदस्यों को गोली मारकर हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस ने कहा कि यह केवल प्रारंभिक आशंका है और अभी पूरी गहन जांच जारी है। पुलिस कर्ज, नौकरी से जुड़े तनाव, पारिवारिक दबाव या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कारणों की भी पड़ताल कर रही है।

इसी के साथ पुलिस आसपास के लोगों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के समय घर के बाहर या आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि हुई या नहीं। मृतकों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं और उनकी कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की जा रही है।

इस मामले ने स्थानीय लोगों में गहरा शोक और डर पैदा कर दिया है। पड़ोसी और इलाके के निवासी पुलिस से लगातार घटना की पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने परिवार के अन्य रिश्तेदारों को भी सुरक्षा प्रदान की है और मानसिक समर्थन देने के लिए काउंसलर को बुलाया गया है।

अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि घटना के पीछे कोई बाहरी व्यक्ति शामिल था या यह एक दुखद पारिवारिक आत्महत्या थी। पुलिस यह भी देख रही है कि अमीन के मानसिक स्थिति, वित्तीय या सामाजिक दबाव और पारिवारिक परिस्थितियों का इस घटना में क्या रोल रहा।

घटनास्थल पर मिले तमंचों और गोलियों के निशान की फॉरेंसिक जांच चल रही है। इसके अलावा, पुलिस घटनास्थल पर खून और फिंगरप्रिंट की जांच कर रही है ताकि स्पष्ट रूप से यह तय किया जा सके कि किसने किसको गोली मारी और आत्महत्या की प्रक्रिया कैसी थी।

इस मामले की गहन जांच में कई विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीम शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में कोई भी पहलू नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में ही सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन डेटा और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे मामले की वास्तविकता सामने आएगी।

सहारनपुर की यह घटना समाज और प्रशासन दोनों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि पारिवारिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस घटना के नतीजे में पुलिस और प्रशासन परिवारों के लिए जागरूकता अभियान और सामाजिक सुरक्षा उपाय बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।

प्रारंभिक रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकेगा कि यह सामूहिक हत्या थी या परिवार ने किसी मानसिक दबाव के चलते सामूहिक आत्महत्या की। पुलिस ने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी तरह की अफवाह फैलाने से बचने को कहा है।

सोना वायदा में 4469 रुपये और चांदी वायदा में 14625 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 31 रुपये तेज

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 399151.87 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 121826.48 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 277302.02 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 41869 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 6632.25 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 112484.63 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 145775 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 152500 रुपये और नीचे में 145500 रुपये पर पहुंचकर, 145639 रुपये के पिछले बंद के सामने 4469 रुपये या 3.07 फीसदी की तेजी के संग 150108 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 4647 रुपये या 3.94 फीसदी की मजबूती के साथ 122600 रुपये प्रति 8 ग्राम बोला गया। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 634 रुपये या 4.29 फीसदी की मजबूती के साथ 15424 रुपये प्रति 1 ग्राम बोला गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 145389 रुपये के भाव पर खूलकर, 152545 रुपये के दिन के उच्च और 144811 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 4680 रुपये या 3.22 फीसदी की मजबूती के साथ 149907 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 145569 रुपये के भाव पर खूलकर, 154145 रुपये के दिन के उच्च और 145420 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 145420 रुपये के पिछले बंद के सामने 5259 रुपये या 3.62 फीसदी की मजबूती के साथ 150679 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया।

कमोडिटी वायदाओं में 121826.48 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 277302.02 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 112484.63 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 41869 पॉइंट के स्तर पर

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 306499 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 327998 रुपये और नीचे में 306499 रुपये पर पहुंचकर, 310275 रुपये के पिछले बंद के सामने 14625 रुपये या 4.71 फीसदी बढ़कर 324900 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 15330 रुपये या 4.91 फीसदी की मजबूती के साथ 327757 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 15275 रुपये या 4.89 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 327741 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

मेटल वर्ग में 5333.27 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 9.55 रुपये या 0.73 फीसदी गिरकर 1292.95 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा रु.1.15 या 0.37 फीसदी औंधकर 313.15 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.75 रुपये या 0.55 फीसदी औंधकर 315.85 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 45 पैसे या 0.23 फीसदी की नरमी के साथ 191.4 रुपये प्रति किलो बोला गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4003.85 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5421 रुपये के भाव पर खूलकर, 5455 रुपये के दिन के उच्च और 5368 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 31 रुपये या 0.57 फीसदी की तेजी के संग 5453 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 32 रुपये या 0.59 फीसदी की तेजी के संग 5454 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 324.7 रुपये के भाव पर खूलकर, 349 रुपये के दिन के उच्च और 322.9 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 332.8 रुपये के पिछले बंद के सामने 15.1 रुपये या 4.54 फीसदी की बढ़त के साथ 347.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 15.2 रुपये या 4.57 फीसदी की बढ़त के साथ 347.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 974 रुपये के भाव पर खूलकर, 5 रुपये या 0.52 फीसदी लुढ़ककर 956.5 रुपये प्रति किलो बोला गया। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 54212.30 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 58272.33 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4617.11 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 396.85 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 72.56 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 234.74 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 582.37 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 3409.54 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.96 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.20 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 20686 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 77889 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 28155 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 416567 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 47729 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14609 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 40627 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 104868 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17013 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 38341 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 40272 पॉइंट पर खूलकर, 42688 के उच्च और 40272 के नीचले स्तर को छूकर, 1597 पॉइंट बढ़कर 41869 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 24.8 रुपये की बढ़त के साथ 271.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.75 रुपये की बढ़त के साथ 13.45 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 148000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 2859.5 रुपये की बढ़त के साथ 3790.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 320000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 10455 रुपये की बढ़त के साथ 18400 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6.53 रुपये की गिरावट के साथ 11.99 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 55 पैसे की नरमी के साथ 1.53 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 21.2 रुपये की गिरावट के साथ 209.2 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 776 रुपये की गिरावट के साथ 780 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3646.5 रुपये की गिरावट के साथ 5537 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.51 रुपये की बढ़त के साथ 19.29 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 32 पैसे की नरमी के साथ 0.34 रुपये हुआ।

कच्छ की सरहद डेयरी में है भारत का प्रथम कैमल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, ऊँटनी के दूध की राजभोग आइसक्रीम बनाने वाली देश की एक मात्र डेयरी

▸▸ सहकार से समृद्धि : सरहद डेयरी ने 900 दूध मंडलियों तथा 31,067 पशुपालकों के बैंक खाते खोले, 438 मंडलियों को माइक्रो एटीएम मिले

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भूकंप के बाद कच्छ की हुई कायापलट, सहकारिता क्षेत्र में सरहद डेयरी लाई सकारात्मक परिवर्तन

(जीएनएस)। गांधीनगर : 26 जनवरी, 2001 को आए विनाशकारी भूकंप ने कच्छ को इस हद तक तबाह किया कि हरेक के मन में प्रश्न था कि कच्छ फिर से उठ खड़ा हो पाएगा या नहीं। हालाँकि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस प्रदेश की ऐसी कायापलट हुई कि कच्छ विकास, आत्मनिर्भरता तथा सहकारी समृद्धि का उत्तम उदाहरण बन गया है। उनके नेतृत्व में कच्छ पर्यटन, कृषि, सहकारिता जैसे क्षेत्रों में अग्रसर जिला बना है। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में कच्छ की विकास यात्रा को और गति मिली है। उल्लेखनीय है कि भूकंप के बाद कच्छ के सहकारिता क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में 'श्री कच्छ जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ' यानी सरहद डेयरी की उल्लेखनीय भूमिका रही है। 2009 में श्री वलमजी हुंबल द्वारा स्थापित सरहद डेयरी कच्छ की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है और जिले के पशुपालकों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है।

सरहद डेयरी 80,000 दूध उत्पादकों से प्रतिदिन 5.5 लाख लीटर दूध प्राप्त करती है

सरहद डेयरी 900 से अधिक सहकारी मंडलियों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 80,000 दूध उत्पादकों से लगभग 5.5 लाख लीटर दूध एकत्र करती है। डेयरी में प्रतिदिन 4 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होती है और यहाँ 300 टन क्षमता का पशु आहार (कैटल फीड) प्लांट भी है। इसके अतिरिक्त; डेयरी द्वारा प्रतिदिन 50,000 लीटर आइसक्रीम भी बनाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन 3.38 लाख लीटर प्रतिदिन दर्ज हुआ है। डेयरी द्वारा पशुपालकों को प्रतिदिन अनुमानित 3 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान सरहद डेयरी ने 1,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक टर्नओवर हासिल किया है, जो वार्षिक 9.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सरहद डेयरी हरियाणा, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अमूल के डेयरी प्लांट को भैंस के शुद्ध दूध की आपूर्ति करने में भी अग्रसर है।

'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार कर रही है सरहद डेयरी

'सहकार से समृद्धि' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की एक दूरदर्शी पहल है। इस कार्यक्रम अंतर्गत सरहद डेयरी ने कच्छ जिला मध्यस्थ सहकारी (केडीसीसी) बैंक में 900 दूध मंडलियों तथा 31,067 पशुपालकों की बैंक खाते खोलने में सहायता की है। बैंकिंग को अधिक सरल बनाने के लिए किसानों को रुपे कार्ड दिए गए हैं और 438 दूध मंडलियों को माइक्रो एटीएम प्राप्त हुए हैं।

सरहद डेयरी में है भारत का प्रथम कैमल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट

कच्छ के रण का सफेद सोना माने जाने वाले ऊँटनी के दूध में भरपूर खाद्य खनिज तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायी हैं और रोगप्रतिकारक शक्ति में वृद्धि करते हैं। भारत का सर्वप्रथम ऊँटनी के दूध को दुर्गंधमुक्त करने का प्रोसेसिंग प्लांट कच्छ में यानी सरहद डेयरी के पास है, जो 16 जनवरी 2019 से कार्यरत है। ऊँटनी के दूध के लिए प्राथमिक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी सरहद डेयरी ने प्राप्त किया है। कच्छ जिले में रापर, नखत्राणा, गढशीशा तथा कोटडा आथमणा; इन चार कलेक्शन केन्द्रों के माध्यम से ऊँटनी के दूध का अमूल पैटर्न के अनुसार कलेक्शन किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान ऊँटनी के दूध का दैनिक संग्रहण 4,754 लीटर हुआ है। ऊँटनी का दूध जमा कराने वाले ऊँटपालकों को वार्षिक 8,72,83,440 रुपए का भुगतान किया गया है, जिससे 350 से अधिक ऊँटपालक परिवारों को लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त; समग्र भारत में ऊँटनी के दूध की राजभोग फ्लेवर की आइसक्रीम केवल सरहद डेयरी में ही बनाई जाती है। 22 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस आइसक्रीम प्लांट का उद्घाटन किया गया था और इस प्लांट द्वारा केवल एक ही वर्ष में 80 वेराइटी लॉन्च की गई हैं। वर्ष 2024-25 में कुल 24.52 लाख लीटर आइसक्रीम का उत्पादन किया गया और अधिकतम् डिसपैच 58,000 लीटर दर्ज हुआ है।

सरहद डेयरी को मिली है वैश्विक पहचान

जनवरी 2022 में गांधीनगर में इंडियन डेयरी एसोसिएशन (आईडीए) कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी; जिसमें सरहद डेयरी ने भाग लिया था, तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन (आईडीएफ) द्वारा केरल राज्य के कोच्चिं में विश्व में पहली बार आयोजित रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस 2024 में विश्व में ऊँट तथा ऊँटनी के विषय पर आयोजित एक महत्वपूर्ण सत्र में सरहद डेयरी द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऊँटनी के दूध की प्रोसेसिंग तथा उत्पादों में किए गए उत्कृष्ट कामकाज का विश्व स्तर पर संज्ञान लिया गया। इसी प्रकार; सरहद डेयरी को 2025 में दुबई में आयोजित विश्व के सबसे बड़े फूड शो 'गल्फ फूड एक्सपो' में भी वैश्विक स्तर पर पहचान मिली, जहाँ अमूल के स्टॉल पर ऊँटनी के दूध के उत्पादकों ने विशेष आकर्षण जमाया। सरहद डेयरी को उसके प्रशंसनीय कामकाज के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं; जिनमें सामाजिक विकास तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए FOKIA Award 2014, कच्छ डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए रोटरी क्लब वॉकेशनल एक्सीलेंस अवॉर्ड 2017, एग्रीटेक में उत्कृष्टता के लिए FOKIA Award 2024 तथा टिकाऊ प्रदर्शन के लिए VNM TV की ओर से ग्रीन वर्कप्लेस अवॉर्ड 2025 शामिल हैं।

विश्व आर्थिक मंच : 2026, दावोस

गुजरात एआई, डिफेंस, टेक्सटाइल पार्क्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और इनोवेटिव फाइनेंसिंग जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों की तलाश कर रहा है : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

(जीएनएस)। गांधीनगर : विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की 56वीं वार्षिक बैठक 19 से 23 जनवरी, 2026 के दौरान स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हो रही है। इस वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए गुजरात की ओर से उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। यहां इंडिया पवेलियन के अंतर्गत देश के 10 राज्यों के प्रतिनिधिमंडल उपस्थित हैं, जो भारत में निवेश के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को पेश कर निवेशकों के साथ चर्चा करेंगे।

इस अवसर पर गुजरात की ओर से उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात सौभाग्यशाली है कि उसे शुरुआत से ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का लाभ मिला है और 2014 के बाद पूरा देश उनके नेतृत्व में विकास कर रहा है। अभी विश्व आर्थिक मंच में भारत का सबसे बड़ा और मजबूत प्रतिनिधिमंडल देखने को मिला है और जब हम तड़के यहां पहुंचे, तब पूरी दुनिया विश्राम में थी, लेकिन भारत के राज्यों के प्रतिनिधिमंडल सक्रिय रूप से निवेशकों के साथ बैठक में व्यस्त थे। यह हमारी प्रतिबद्धता, हमारी कार्य संस्कृति और देश के लोगों के प्रति हमारे नेतृत्व के समर्पण को दिखाता है।

▸▸ विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन

▸▸ गुजरात की ओर से उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की बैठकें

▸▸ गुजरात सौभाग्यशाली है कि उसे शुरुआत से ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का लाभ मिला है, हम यहां गुजरात के लिए नए मौकों की तलाश में आए हैं : श्री हर्ष संघवी

निवेश के लिए गुजरात की क्षमता को उजागर करते हुए श्री हर्ष संघवी ने आगे कहा कि गुजरात में निवेश की मजबूत परंपरा रही है। वाइब्रेंट गुजरात 2024 में राज्य में 45 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए थे, और पिछले तीन महीनों में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत राज्य में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात का प्रतिनिधिमंडल यहां कुछ नया सीखने और नए अवसरों की तलाश में आया है।

श्री संघवी ने आगे कहा कि हम यहां अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधिमंडल के रूप में नहीं, बल्कि हम एक देश के रूप में एक ही एजेंडे के साथ यहां उपस्थित हैं। हम सभी यहां अपना कौशल, अपनी क्षमताएं और अपना सुशासन प्रस्तुत करेंगे। गुजरात राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिफेंस, टेक्सटाइल पार्क्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और इनोवेटिव फाइनेंसिंग जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों की तलाश कर रहा है।

फर्जी बिलों का जाल और 658 करोड़ का खेल बहु-राज्यीय जांच में ईडी का बड़ा शिकंजा

(जीएनएस)। देश में जीएसटी व्यवस्था को पारदर्शी और कर चोरी से मुक्त बनाने के दावों के बीच फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला एक बार फिर जांच एजेंसियों के सामने गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। अरुणाचल प्रदेश से जुड़े 658 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी आईटीसी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को एक साथ कई राज्यों में छापेमारी कर पूरे कारोबारी नेटवर्क को हिला दिया। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई इस कार्रवाई में झारखंड, पश्चिम बंगाल और मणिपुर समेत कई स्थानों पर संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों के ठिकानों की तलाशी ली गई। यह अभियान न केवल राशि के लिहाज से बड़ा है, बल्कि इस बात का भी संकेत देता है कि फर्जी बिलिंग और टैक्स क्रेडिट के दुरुपयोग का नेटवर्क कितनी गहराई तक फैला हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, ईडी की यह कार्रवाई अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ी है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आईटीसी का अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि राकेश शर्मा और आशुतोष कुमार झा नामक दो व्यक्तियों ने बिना किसी वास्तविक वस्तु या सेवा की आपूर्ति किए बड़े पैमाने पर फर्जी बिल तैयार किए। इन बिलों के जरिए न केवल कागजों पर कारोबार दिखाया गया, बल्कि जीएसटी प्रणाली का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये का टैक्स क्रेडिट भी हासिल किया गया। यही राशि बाद में विभिन्न खातों और फर्मों के माध्यम से इधर-उधर घुमाई गई, जिससे धन शोधन का संदेह और गहराता चला गया।

जांच एजेंसियों का ध्यान विशेष रूप से 'सिद्धि विनायक ट्रेड मर्चेंट्स' नामक एक कथित फर्जी फर्म पर केंद्रित है। आरोप है कि इस फर्म के जरिए लगभग 658.55 करोड़ रुपये के जाली बिल जारी किए गए और इसके आधार पर करीब 99.31 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया। कागजों में यह सब वैध लेन-देन जैसा दिखता रहा, लेकिन जमीनी स्तर पर न तो कोई वास्तविक सप्लाई हुई और न ही कोई वास्तविक व्यापारिक गतिविधि। ईडी का मानना है कि यह फर्म केवल एक मुखौटा थी, जिसके पीछे पूरा नेटवर्क सक्रिय था।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े करीब 58 अन्य फर्जी कारोबारी प्रतिष्ठान विभिन्न राज्यों में सक्रिय थे। ये सभी आपस में जुड़े हुए थे और एक-दूसरे को फर्जी बिल जारी कर जीएसटी प्रणाली को भ्रमित करने का काम कर रहे थे। इस नेटवर्क की खास बात यह थी कि अलग-अलग राज्यों में छोटी-छोटी फर्मों और कंपनियों के नाम पर कारोबार दिखाया जाता था, जिससे संदेह कम हो और जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके।

पश्चिम रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस एवं जबलपुर के बीच स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को समायोजित करने के उद्देश्य से ट्रेन संख्या 02133/02134 बांद्रा टर्मिनस–जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 02133 बांद्रा टर्मिनस–जबलपुर स्पेशल तथा ट्रेन संख्या 02134 जबलपुर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को अगली सूचना तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 02133 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 22 जनवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के ऑनलाइन निवारण का जनवरी महीने का राज्य स्तरीय 'स्वागत' गुरुवार, 22 जनवरी को आयोजित होगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हर महीने आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी-2026 का राज्य स्तरीय 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) गुरुवार, 22 जनवरी को आयोजित होगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2003 से शुरू हुए स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम के तहत हर महीने के चौथे गुरुवार को राज्य स्तरीय 'स्वागत' का आयोजन किया जाता है।

तदनुसार, जनवरी-2026 के राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम के लिए नागरिक अपना अभ्यावेदन गुरुवार, 22 जनवरी की सुबह 8.00 से 11.00 बजे के दौरान मुख्यमंत्री की जनसंपर्क इकाई, स्वर्णिम संकुल-2, गांधीनगर में व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार दोपहर बाद इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' में स्वयं मौजूद रहकर नागरिकों की शिकायतें सुनेंगे।

अनुशासन का संदेशः सेल की सख्त कार्रवाई से ठेकेदारी व्यवस्था में हलचल

(जीएनएस)। देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने हाल के दिनों में एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए 21 फर्मों और ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सार्वजनिक उपक्रमों में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सेल प्रबंधन ने यह कार्रवाई देशभर में फैली अपनी विभिन्न इकाइयों और कॉरपोरेट स्तर पर सामने आए गंभीर अनियमितताओं के मामलों के बाद की है, जिनमें अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन, जाली दस्तावेजों की प्रस्तुति, भ्रष्ट आचरण, असंतोषजनक प्रदर्शन और श्रमिकों के वेतन से जुड़ी गड़बड़ियां प्रमुख रूप से शामिल हैं।

सेल के इस फैसले से न केवल संबंधित ठेकेदारों और फर्मों में खलबली मच गई है, बल्कि अन्य कंपनियों और सेवा प्रदाताओं के लिए भी यह एक चेतावनी के रूप में सामने आया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करना केवल व्यावसायिक अवसर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और नियमों के प्रति प्रतिबद्धता की भी मांग करता है। सेल ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता, धोखाधड़ी या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे संबंधित फर्म कितनी ही बड़ी या प्रभावशाली क्यों न हो। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई भिलाई, राउरकेला, बोकारो और इस्को स्टील प्लांट के साथ-साथ सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेट कार्यालय से जुड़े मामलों में की गई है। अलग-अलग इकाइयों में जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर ठेकेदारों और फर्मों की भूमिका का मूल्यांकन किया गया और उसके बाद यह सख्त निर्णय लिया गया। सेल प्रबंधन का कहना है कि कंपनी की कार्यप्रणाली में गुणवत्ता, समयबद्धता और नैतिकता सर्वोपरि है, और जो भी इन मूल सिद्धांतों से समझौता करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। भिलाई स्टील प्लांट से सबसे अधिक 11 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि राउरकेला से चार, बोकारो से आठ और इस्को स्टील प्लांट से छह कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तीन ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की गई है। यह आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि समस्या किसी एक इकाई या क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि विभिन्न स्तरों पर अनुशासन और अनुपालन से जुड़ी खामियां सामने आईं।

सेल के निर्देशों के अनुसार इन फर्मों पर अलग-अलग अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ ठेकेदारों को 2026 से 2028 तक के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि कुछ पर वर्ष 2100 तक का स्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। स्थायी प्रतिबंध का निर्णय उन मामलों में लिया गया है, जहां अनियमितताएं गंभीर और बार-बार दोहराई गईं या जहां जाली दस्तावेजों और धोखाधड़ी जैसे मामलों में ठोस प्रमाण मिले। यह फैसला दर्शाता है कि सेल अब केवल अस्थायी चेतावनियों या हल्की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य में ऐसे तत्वों को पूरी तरह से बाहर करने की नीति पर काम कर रहा है।

इस्को स्टील प्लांट के जनसंपर्क अधिकारी भास्कर कुमार ने बताया कि जिन फर्मों पर यह कार्रवाई हुई है, वे या तो अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहीं या जांच के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी पाए गए।

चलती ट्रेन में छूटा यात्री का बैग वाणिज्य विभाग एवं आरपीएफ की सतर्कता से सुरक्षित मिला

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल से संचालित ट्रेन संख्या 11465 वेरावल–जबलपुर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री का बैग ट्रेन से उतरते समय छूट गया, जिसे वाणिज्य विभाग के कर्मचारी एवं रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की तत्परता से सुरक्षित कर यात्री को सौंप दिया गया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यात्री श्री अशोक भाई चंद्रवाडिया, निवासी उपलेटा, दिनांक 19.01.2026 को गाड़ी संख्या 11465 के कोच बी-2 में राजकोट से चांदलोडिया की यात्रा कर रहे थे। चांदलोडिया स्टेशन पर उतरते समय उनका एक बैग दरवाजे पर ही छूट गया।

ड्यूटी पर तैनात चल टिकट निरीक्षक (टीटीआई) श्री एम. एफ. अकरम ने लावारिस अवस्था में बैग को देखकर यात्रियों से उसके संबंध में पूछताछ की। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उन्होंने तत्काल आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ एस्कॉर्ट स्टाफ श्री मनीष जाट एवं श्री बदन सिंह ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए बैग को सुरक्षित कब्जे में लिया और नियमानुसार जांच की। जांच के दौरान बैग में लगभग 50,000 नकद एवं अन्य आवश्यक सामान पाया गया। बैग की कुल अनुमानित कीमत लगभग 52,000 थी।

पीएनआर एवं उपलब्ध संपर्क विवरण के आधार पर यात्री से संपर्क कर उन्हें सूचना दी गई। आवश्यक औपचारिकताओं के पश्चात यात्री को अहमदाबाद बुलाकर बैग एवं समस्त सामग्री सुरक्षित रूप से सुपुर्द की गई।

यात्री श्री अशोक भाई चंद्रवाडिया ने आरपीएफ एवं टीटीआई की ईमानदारी, सतर्कता एवं सराहनीय कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने भावनगर मंडल के कर्मचारियों की सतर्कता एवं ईमानदारी की सराहना करते हुए कहा कि पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल अपने सम्मानित यात्रियों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

भावनगर मंडल में दिवंगत रेल कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता

(जीएनएस)। भावनगर मंडल में रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों, विशेषकर रेल सेवा के दौरान आकस्मिक निधन की स्थिति में त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंडल प्रशासन द्वारा डिविजनल स्टाफ रिलीफ एंड वेलफेयर फंड (DSRWF) का गठन किया गया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 20 जनवरी 2026 को रेल सेवा के दौरान निधन होने वाले 08 रेल कर्मचारियों के परिवारों को प्रत्येक परिवार हेतु 50,000/- (पचास हजार रुपये) की सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। यह चेक DSRWF के संरक्षक एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के कर-कमलों से वितरित किए गए। इसके अलावा परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु जरूरी आवेदन और कार्यवाही, HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करने के संदर्भ में मार्गदर्शन भी दिया गया ।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तथा वे स्वयं भी उपस्थित रहे। मंडल प्रशासन द्वारा दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि रेलवे अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहेगा।

ऑपरेटिंग विभाग की टीम बनी डीआरएम कप-2026 चैम्पियन

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल की ऑपरेटिंग विभाग की टीम ने डीआरएम कप 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। प्रतापनगर में माधव राव सिंधिया स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में ऑपरेटिंग विभाग की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग की टीम को 7 विकेट से हराकर डीआरएम कप पर कब्जा किया।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 08 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 तक आयोजित इस टूर्नामेंट में वडोदरा मंडल के विभिन्न विभागों की कुल 16 टीमों ने खेल भावना के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच विद्युत(ट्रैक्शन)विभाग एवं ऑपरेटिंग विभाग की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें ऑपरेटिंग विभाग की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और "डीआरएम ट्रॉफी–2026" की चैम्पियन बनी।

वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक एवं वडोदरा मंडल खेलकूद संघ के अध्यक्ष श्री राजू भडके ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की और साथ ही टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मोमेंटो एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि रेल कर्मियों को अपनी ड्यूटी के साथ-साथ खेलकूद गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए, जिससे वे स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें।

इस प्रतियोगिता में सुरक्षा विभाग के श्री मीठाभाई को बेस्ट बॉलर एवं ऑपरेटिंग विभाग के श्री महेंद्र देसाई ने बेस्ट बैट्समैन का ख़िताब जीता। ऑपरेटिंग विभाग के श्री कार्तिक को मैन ऑफ द सीरीज का ख़िताब दिया गया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के मार्गदर्शन में वीडीएसए द्वारा इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री नीरज धमीजा, वीडीएसए के सचिव श्री प्रदीप मीणा एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे।